प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

12-दिसंबर-2018 12:12 IST

पीएमएफबीवाई के प्रीमियम में कमी

प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत, किसानों द्वारा देय प्रीमियम को काफी कम और सरल बना दिया गया है और किसानों के लिए पैन-इंडिया आधार पर एक प्रीमियम दर है जो अधिकतम 1.5% है, रबी, खरीफ और वार्षिक बागवानी / वाणिज्यिक फसलों के लिए क्रमशः 2% और 5% बीमा राशि।

किसानों के लाभ के लिए फसल बीमा एक प्रमुख जोखिम शमन उपकरण है। बीमा सभी अवधि और क्षेत्र में जोखिम फैलाने के बारे में है। बीमाकर्ता अच्छे सत्रों / वर्षों में प्रीमियम की बचत करते हैं और यदि अच्छे वर्षों में की गई बचत से बुरे वर्षों में, यदि कोई हो, तो उच्च दावों का भुगतान करते हैं। 2016-17 में किसानों से 41616.04 करोड़ रुपये की राशि एकत्र किए गए प्रीमियम के मुकाबले रु। किसानों को 16279.25 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसी तरह, किसानों से 3038.70 करोड़ की राशि एकत्र किए गए प्रीमियम के मुकाबले 2017-18 (खरीफ 2017) के दौरान रु .6967.92 करोड़ का दावा किया गया है। बीमा कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रीमियम का विवरण और पिछले तीन सत्रों के दौरान किसानों को भुगतान किया गया दावा निम्नानुसार है।

(करोड़ रुपए में)

ऋतु	सकल प्रीमियम प्राप्त हुआ	सकल प्रीमियम में किसानों का योगदान	कुल दावे
2016-17	22345.51	4216.04	16279.25
2017-18 (केवल खरीफ 17)	19767.46	3038.70	16967.92

पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के पहले दो वर्षों के दौरान समग्र अच्छे मानसून के बावजूद, 2016-17 के दौरान दावा अनुपात लगभग 73% और खरीफ 2017 के दौरान लगभग 86% है। इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन के लिए बीमा कंपनी के लिए प्रशासनिक और अन्य लागत 10-12% से होती है। इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन के लिए बीमा कंपनी के लिए प्रशासनिक और अन्य लागत सकल प्रीमियम का 10% से 12% तक है। इसके अलावा, अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों / राज्यों में किसानों ने उच्च दावे प्राप्त किए और इन राज्यों में दावा अनुपात अधिक था। केरल 210% और कर्नाटक-132%, खरीफ 2016 के दौरान, तमिलनाडु - 287% और आंध्र प्रदेश 159% रबी 2016-17 के दौरान। इसी तरह खरीफ 2017 के दौरान, उच्च दावा अनुपात छत्तीसगढ़ राज्यों में - 425%, हरियाणा - 201%, मध्य प्रदेश - 135% और ओडिशा - 204% है।

यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने दी।

*****

ए पी एस / आरसीएस